राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6148/2024

नाहिद अख्तर पत्नी सैयद जफर मोहम्मद शाह, उम्र लगभग 34 वर्ष, 5-ई-256, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर जिला बीकानेर।---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

2. जफर मोहम्मद शाह पुत्र स्वर्गीय श्री हसन शाह, उम्र लगभग 47 वर्ष, जलालसर, तहसील जामसर, जिला बीकानेर। ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री कुणाल बिश्नोई।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री एसआर चौधरी, पीपी।

श्री आरएस चौधरी और श्री जेके सुथार।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>10/09/2024</u>

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 494 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन जामसर, जिला बीकानेर में दर्ज एफआईआर

संख्या 35/2024, दिनांक 16.03.2024 को रद्द करने की मांग की गई है। एफआईआर प्रतिवादी संख्या 2 के पति द्वारा अपनी पत्नी/याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज कराई गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि उसने उसके साथ अपने विवाह के दौरान दूसरी बार पुनर्विवाह किया है।

2. संक्षेप में कहा जाए तो याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता (पति-प्रतिवादी 2) ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उसने याचिकाकर्ता (पत्नी) से 22.10.2008 को इस्लामी कानून के तहत विवाह किया था। उनकी शादी से उनकी दो बेटियां हैं। शादी के बाद से ही याचिकाकर्ता (पत्नी) ने कथित तौर पर उस पर हावी रही, उसे अपने परिवार के साथ रहने के लिए मजबूर किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उनकी शादी टूट गई। एक समय पर उन्होंने 15.03.2017 को एक समझौता विलेख निष्पादित करके मामले को सुलझा लिया, जिसके तहत शिकायतकर्ता (पति) ने याचिकाकर्ता (पत्नी) को उसके और उनकी बेटियों के लिए एकमुश्त निपटान/मुआवजे के रूप में ₹5,30,000/- का भुगतान किया।

2.1 समझौता होने के बाद, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी भी कर ली। याचिकाकर्ता ने 06.07.2018 को तलाक का मुकदमा दायर किया, जिसे केस नंबर 87/2018 के रूप में पंजीकृत किया गया, जो अभी भी लंबित है। याचिकाकर्ता (पत्नी) ने कथित तौर पर असलम से शादी करने के बाद उसके साथ रहना शुरू कर दिया। उसने असलम से अपनी शादी को छिपाते हुए धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन दायर किया। अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया गया, लेकिन चूंकि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 ने भुगतान नहीं किया, इसलिए याचिकाकर्ता ने धारा 125 (3) सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण आदेश के प्रवर्तन के लिए एक और आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता का मामला यह है

कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि धारा 125 और 127 सीआरपीसी के तहत पारित आदेशों के अनुपालन से बचने की एक रणनीति है। इसलिए तत्काल याचिका।

3. उपर्युक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंदी पक्ष की दलीलें सुनी हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ़ विचाराधीन एफआईआर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से याचिकाकर्ता पर अनुचित दबाव डालने की एक चाल प्रतीत होती है। पक्षकार पहले से ही विवाह विच्छेद और भरण-पोषण के संबंध में मुकदमे में हैं। एफआईआर याचिकाकर्ता को परेशान करने और उसे अवैध मांगों का अनुपालन करने के लिए मजबूर करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रतीत होती है।

4.1. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 का वैवाहिक विवाद न्यायाधीन है और इसके लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। दिनांक 01.03.2019 के अंतरिम भरण-पोषण आदेश के तहत, शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता और उसकी बेटियों को 16,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। एफआईआर पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित बाध्यकारी भरण-पोषण आदेश को कमजोर करने के लिए है, जो अंतिम हो गया है। यदि शिकायतकर्ता पारिवारिक न्यायालय के आदेश से व्यथित है, तो उसे जवाबी हमले के रूप में झूठी एफआईआर दर्ज कराने के बजाय सक्षम न्यायालय में इसे चुनौती देनी चाहिए।

4.2. विद्वान वकील ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा कथित रूप से दूसरी शादी का पता चलने के बाद एफआईआर दर्ज करने में छह महीने की देरी के कारण एफआईआर रद्द की जानी चाहिए। बिना किसी स्पष्टीकरण के

यह देरी याचिकाकर्ता को परेशान करने की रणनीति का संकेत देती है। वास्तव में, यह शिकायतकर्ता ही है जिसने 07.06.2018 को दूसरी शादी की है।

5. उपरोक्त तर्कों का विद्वान लोक अभियोजक और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील द्वारा पुरजोर विरोध किया जाता है।

6. स्वीकार किया जाता है कि शिकायतकर्ता का दावा है कि वह याचिकाकर्ता का वैध पति है। उनका आरोप है कि चूंकि उनकी पत्नी ने दूसरी शादी की थी और इस तथ्य का खुलासा अंतरिम भरण-पोषण देने वाली अदालत के समक्ष नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसने आईपीसी की धारा 406 का अपराध किया है। यह समझ से परे है कि कैसे आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत अपराध केवल इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि पति को प्रथम दृष्टया या अन्यथा किसी सबूत के बिना लगता है कि उसकी पत्नी ने दूसरी बार शादी की है। अधिक से अधिक, भले ही यह माना जाए कि पति इस धारणा को पोषित करने में सही है - चाहे सही हो या गलत - याचिकाकर्ता पत्नी ने दूसरी बार शादी की है, सबसे खराब स्थिति में आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह का अपराध आकर्षित होता है।

7. यह सामान्य कानून है कि आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और संपत्ति सौंपने के लिए प्रलोभन से उत्पन्न होती है और आईपीसी की धारा 406 संपत्ति को ट्रस्ट में सौंपने और उसके बाद ऐसे ट्रस्ट के उल्लंघन से उत्पन्न होती है। वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी आवश्यक तत्व उन प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए नहीं बनाया गया है। इस प्रकार, आरोपित एफआईआर में आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों को शामिल करना कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है। इन अपराधों (आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत) के लिए, एफआईआर टिकने योग्य नहीं है।

8. तदनुसार, वर्तमान याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 420 और 406 के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन जामसर, जिला बीकानेर में दर्ज एफआईआर संख्या 35/2024 दिनांक 16.03.2024 को आंशिक रूप से रद्द किया जाता है और इसके बाद परिणाम भुगतने होंगे।

9. मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि जांच अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य 1 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करे।

10. याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। यदि जांच के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है, जो प्रथम दृष्टया उसके द्वारा किए गए किसी संज्ञेय अपराध का संकेत देती है, जिसके लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है, तो उसे बीएनएसएस की धारा 35 के तहत एक सप्ताह का पूर्व नोटिस दिया जाएगा, ताकि वह कानून के अनुसार कानूनी उपाय कर सके।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।